NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 24-06-2025

विषय सूची

» 2024-25 में बाल श्रम बचाव: C-LAB
» ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के पश्चात् IAEA के सामने चुनौतियाँ
» वैश्विक तम्बाकू महामारी पर WHO की 10वीं रिपोर्ट
» 2026 में प्रथम बार घरेलू आय सर्वेक्षण
» भारत-आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा
» यीस्ट से पता चलता है कि भौतिकी उत्परिवर्तन के बिना बहुकोशिकीय जीवन को जन्म दे सकती है

संक्षिप्त समाचार

» अम्बुबाची मेला
» सुवर्णरेखा नदी
» कतर
» 'नव्या' पहल
» ई-रक्त कोष
» वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार
» ग्वाडा नेगेटिव
» भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की आलोचना की
» इफको, ब्राजील में प्रथम विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी

2024-25 में बाल श्रम बचाव: C-LAB

संदर्भ

- हाल ही में, सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज (C-LAB) ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) नेटवर्क के साथ साझेदारी में वर्ष 2024–25 के दौरान बाल श्रमिकों के बचाव से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट की प्रमुख जानकारी

- अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 53,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया।
- तेलंगाना 11,063 बचावों के साथ शीर्ष पर रहा, इसके बाद बिहार (3,974), राजस्थान (3,847), उत्तर प्रदेश (3,804), और दिल्ली (2,588) का स्थान रहा।

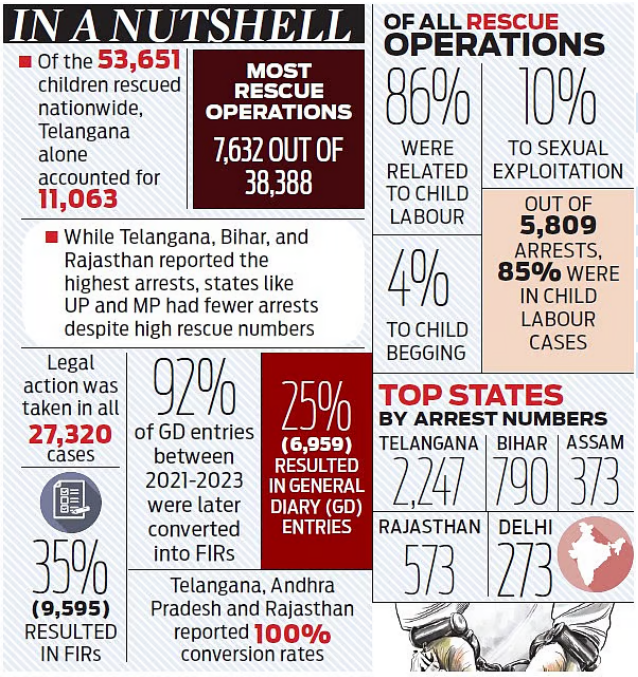

- **चिंताजनक प्रवृत्तियाँ** : रिपोर्ट में बताया गया कि 10 से 14 वर्ष के बीच के लगभग 90% बच्चों को ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत पाया गया जिन्हें सबसे खराब प्रकार के बाल श्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया है — जैसे कि स्पा, मसाज पार्लर और ऑर्केस्ट्रा।
- **कानूनी कार्रवाई और प्रवर्तन:** कुल 38,388 एफआईआर दर्ज की गईं और 5,809 गिरफ्तारियाँ हुईं, जिनमें से 85% गिरफ्तारियाँ सीधे बाल श्रम से संबंधित थीं।
  - तेलंगाना, बिहार और राजस्थान प्रवर्तन में अग्रणी रहे।
  - उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बचाव की संख्या अधिक थी, लेकिन गिरफ्तारी की दर कम रही।
- **नीतिगत अनुशंसाएँ:** रिपोर्ट में "बाल श्रम समाप्ति हेतु राष्ट्रीय मिशन" शुरू करने, जिला-स्तरीय "बाल श्रम टास्क फोर्स" के गठन और गैर-सरकारी संगठनों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की सिफारिश की गई है ताकि अभियोजन और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।

बालक की परिभाषा

- *संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNHRC)* के अनुसार: 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति "बालक" माना जाता है।
  - भारत 1992 से इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) **के अनुसार:** कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम है, "बालक" कहलाता है।
  - ILO के अनुसार बाल श्रम ऐसा कार्य है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता एवं गरिमा से वंचित करता है, और उनके शारीरिक और/या मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है।

बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 15(3) **(संरक्षणात्मक भेदभाव):** राज्य को बालकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 21A **(शिक्षा का अधिकार):** 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 24**:** 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्रियों, खानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित करने पर प्रतिबन्ध लगाता है।
- अनुच्छेद 39(e) और 39(f)**:**

- बच्चों को उनकी आयु या शक्ति के अनुपयुक्त व्यवसायों में आर्थिक मजबूरी से जाने से रोका जाए।
- बचपन और युवावस्था का शोषण तथा नैतिक एवं भौतिक उपेक्षा से संरक्षण किया जाए।

- अनुच्छेद 45: छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश देता है।

कानूनी संरक्षण

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 **(1986 में संशोधित):** "बालक" वह है जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो।
- बाल श्रम (प्रतिबंधन एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016:
  - सभी व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करने और किशोरों (18 वर्ष से कम) को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है।
  - इस कानून के उल्लंघन पर जुर्माना और दंड का प्रावधान है।

क्या आप जानते हैं?

- *गुरुपदस्वामी समिति (1979)* ने पाया कि बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है।
  - समिति ने बच्चों के लिए बहु-आयामी नीति अपनाने की सिफारिश की थी।
- इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1986 में बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम लागू हुआ।

भारत में बाल श्रम के कारण

- गरीबी और आर्थिक मजबूरी: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, गरीबी बाल श्रम का मुख्य कारण बनी हुई है।
  - बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्षरत परिवार प्रायः घरेलू आय के पूरक के लिए बच्चों पर निर्भर रहते हैं, खासकर ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच का अभाव: *कई बच्चे खराब बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की कमी या वित्तीय बाधाओं के कारण स्कूल छोड़ देते हैं।*
  - *स्कूल से बाहर निकलने के बाद, उनके कार्यबल में शामिल होने की संभावना अधिक होती है।*
- अशिक्षा और जागरूकता की कमी: सीमित शिक्षा वाले माता-पिता स्कूली शिक्षा के दीर्घकालिक मूल्य या बाल श्रम के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं।
  - यह शोषण के चक्र को बनाए रखता है।

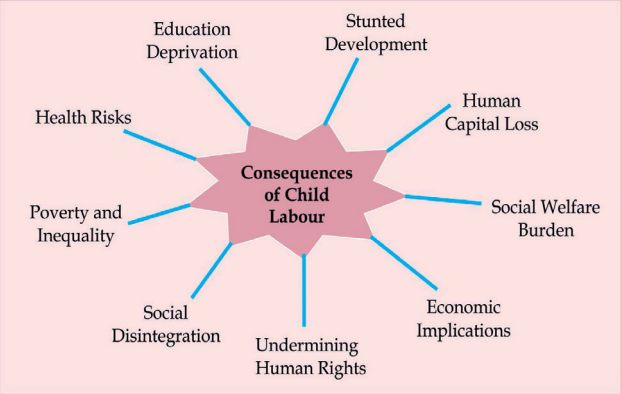

- सस्ती मजदूरी की मांग: बीड़ी निर्माण, कालीन बुनाई, पटाखा उद्योग जैसे क्षेत्रों में बच्चों को कम वेतन और कुशलता के कारण वरीयता दी जाती है।
- सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएँ: कुछ समुदायों में बाल श्रम को सामान्य माना जाता है या इसे एक संस्कार के रूप में भी देखा जाता है।
  - विशेषकर लड़कियों को छोटी उम्र में ही घरेलू कार्य या देखभाल करने वाली भूमिकाओं में लगाया जा सकता है।
- प्रवासन और तस्करी:हाशिए पर पड़े समुदायों के बच्चों की प्रायः तस्करी की जाती है या वे अपने परिवारों के साथ शहरी क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं, जहां उन्हें कानूनी सुरक्षा के बिना शोषणकारी रोजगारों में लगा दिया जाता है।

राज्य स्तरीय मॉडल कार्य योजनाएँ

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को प्रवर्तन, बचाव और पुनर्वास के लिए मॉडल योजनाएँ प्रदान की हैं।

- सहयोगी बाल श्रम विरोधी प्रयास (SAFAL): प्रवर्तन और सामुदायिक निगरानी को मजबूत करने के लिए शुरू की गई योजना।
- राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (1987):
  - खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - कल्याणकारी योजनाओं का समेकन कर श्रमिक बच्चों के परिवारों को सहायता।
  - उच्च घटनाओं वाले क्षेत्रों में परियोजना-आधारित हस्तक्षेप।
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP):
  - उच्च बाल श्रम वाले जिलों में लागू।
  - विशेष प्रशिक्षण केंद्र, ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा और औपचारिक विद्यालयों में मुख्यधारा में लाने का प्रयास।
  - अब समग्र शिक्षा अभियान में एकीकृत।

सफलता की कहानी

- तेलंगाना के वेलपुर मंडल को समुदाय की भागीदारी, विद्यालयों में बच्चों की निरंतरता और सख्त प्रवर्तन के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन का मॉडल माना गया — यह दर्शाता है कि सतत स्थानीय प्रयासों से क्या कुछ संभव हो सकता है।

Source: IE

ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के पश्चात् IAEA के सामने चुनौतियाँ

समाचार में

- ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ सहयोग निलंबित करने के विधेयक पर विचार कर रहा है, क्योंकि एजेंसी निष्पक्ष रहने और अपने दायित्वों को पूरा करने में कथित रूप से विफल रही है।

पृष्ठभूमि

- यह घोषणा वियना में IAEA की आपातकालीन गवर्निंग बोर्ड की बैठक के दौरान की गई, जो अमेरिका द्वारा ईरान के फोर्डो, नतांज़ और इस्फहान में परमाणु ठिकानों पर हमलों तथा इससे पहले इज़राइल द्वारा अराक हैवी वॉटर रिएक्टर पर किए गए हमले के बाद हुई।
- ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का एक हस्ताक्षरकर्ता है और गैर-परमाणु हथियार राज्य की हैसियत से उसे IAEA के साथ व्यापक सुरक्षा उपाय समझौते में शामिल होना अनिवार्य था, जिसके अंतर्गत एजेंसी को गतिविधियों की निगरानी के लिए अपने उपकरण स्थापित करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें विकिरण स्तरों की निगरानी भी शामिल है।
- ईरान ने IAEA पर राजनीतिक उपकरण बन जाने का आरोप लगाया है और "वस्तुनिष्ठ गारंटी" के बिना सहयोग पुनर्स्थापित न करने की बात कही है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

- यह परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए विश्व का केंद्रीय अंतरसरकारी मंच है।
- 1957 में इसकी स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति आइज़नहावर के 1953 के "एटम्स फॉर पीस" भाषण से प्रेरित होकर हुई थी, जिसका उद्देश्य परमाणु प्रौद्योगिकी से जुड़ी वैश्विक चिंताओं और आशाओं का समाधान करना था।
- यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कार्य करती है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति-सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देती है।

उभरती चुनौतियाँ

- संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के सक्रिय परमाणु स्थलों – नतांज़, इस्फहान और फोर्डो – पर हालिया हमले अभूतपूर्व बढ़त दर्शाते हैं और इससे वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
- यह स्थिति NPT और IAEA की भूमिका को कमजोर कर सकती है, जिससे कूटनीतिक संचार बाधित होता है और परमाणु तनाव बढ़ने का खतरा रहता है।
  - IAEA को इन हमलावर स्थलों तक वर्तमान में कोई पहुंच नहीं है।
- IAEA की निगरानी में आई रुकावट ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार की स्थिति और स्थान की पुष्टि करना

कठिन बना सकती है, जिसमें 400 किलोग्राम यूरेनियम 60% स्तर तक समृद्ध है, जो हथियार-ग्रेड स्तर के पास है।

- यह स्थिति परमाणु सुरक्षा और वैश्विक अप्रसार प्रयासों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती है।

भारत का दृष्टिकोण

- भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
- नाभिकीय सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए, भारत ने संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों को देखते हुए IAEA से क्षति और विकिरण स्तरों पर अद्यतन जानकारी देने का आग्रह किया है।
- भारतीय प्रतिनिधि ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की और भारत की ओर से समर्थन देने की तत्परता दोहराई।

आगे की राह

- वर्तमान परिदृश्य में, IAEA को तकनीकी, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी जटिलताओं का सामना करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को बनाए रखना होगा तथा एक व्यापक परमाणु संकट को टालने का प्रयास करना होगा।

Source: TH

वैश्विक तम्बाकू महामारी पर WHO की 10वीं रिपोर्ट

समाचार में

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट (Global Tobacco Epidemic Report) के 10वें संस्करण को जारी किया है, जिसमें 2008 में MPOWER रणनीति की शुरुआत के बाद से तंबाकू नियंत्रण में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया गया है।
- रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया गया है, जिसमें अब 6.1 अरब से अधिक लोग कम से कम एक MPOWER उपाय की सुरक्षा में हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **व्यापक प्रभाव**: 2007 से अब तक 155 देशों ने कम से कम एक MPOWER नीति अपनाई है, जिससे संयुक्त रूप से 6.1 अरब से अधिक लोगों को लाभ हुआ है।
- **सबसे अधिक प्रगति**: MPOWER उपायों में, सिगरेट पैकेटों पर बड़े ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनी लेबल की सबसे व्यापक और सुसंगत क्रियान्वयन देखा गया है।
- **डिजिटल सामग्री नियंत्रण में भारत की अगुवाई**: भारत विश्व का प्रथम देश बन गया है जिसने डिजिटल स्ट्रीमिंग सामग्री पर विशेष रूप से तंबाकू नियंत्रण नियम लागू किए हैं।
- **TAPS पर भारत का सख्त दृष्टिकोण**: भारत ने सभी प्रकार के मीडिया में तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन (TAPS) पर रोक लगाने के लिए कड़े उपाय लागू किए हैं।
  - यह MPOWER के "E" (Enforce bans) घटक के अनुरूप है और तंबाकू के आकर्षण को कम करने की दिशा में एक अहम कदम है।
- **तंबाकू कर**: रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि तंबाकू कर अब भी वैश्विक स्तर पर सबसे कम अपनाया गया MPOWER उपाय है। यह चिंता का विषय है क्योंकि तंबाकू कर में वृद्धि को विशेष रूप से युवाओं और निम्न-आय वर्गों में तंबाकू सेवन कम करने का सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है।

तंबाकू सेवन

- तंबाकू का उपयोग प्रत्येक वर्ष सात मिलियन से अधिक लोगों की जान लेता है, जिनमें से अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होते हैं।
- भारत, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है।
- भारत फ्ल्यू क्योरड वर्जीनिया (Flue Cured Virginia - FCV) तंबाकू का विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है—चीन, ब्राजील और ज़िम्बाब्वे के बाद।
- भारत में तंबाकू का उपयोग गैर-संचारी रोगों (NCDs) का एक प्रमुख जोखिम कारक है, जैसे कि कैंसर, हृदय

रोग और श्वसन संबंधी बीमारियाँ, जिससे हर साल 13.5 लाख से अधिक मौतें होती हैं।

- विगत दो दशकों में तंबाकू उपयोग के उच्चतम बोझ वाले देशों में इसके उपयोग को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रमुख रणनीतियों में शामिल हैं:
  - फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (FCTC)
  - WHO की छह प्रभावी MPOWER तंबाकू नियंत्रण उपाय:
    - तंबाकू उपयोग और निवारक नीतियों की निगरानी करना;
    - धूम्रपान मुक्त कानूनों द्वारा लोगों को तंबाकू के धुएँ से बचाना;
    - तंबाकू छोड़ने में सहायता प्रदान करना;
    - पैकेट लेबल और जनमाध्यमों के माध्यम से तंबाकू के खतरों की चेतावनी देना;
    - तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध लागू करना;
    - तंबाकू पर कर बढ़ाना।

Source: TH

2026 में प्रथम बार घरेलू आय सर्वेक्षण

प्रसंग

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) वर्ष 2026 में प्रथम बार घरेलू आय सर्वेक्षण (Household Income Survey) आयोजित करेगा।

परिचय

- यह भारत का प्रथम व्यापक, राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण होगा जो पूरी तरह से घरेलू आय पर केंद्रित होगा, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।
- **प्रमुख एजेंसी**: यह सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा किया जाएगा।
- **तकनीकी विशेषज्ञ समूह (TEG)**: MoSPI द्वारा गठित यह समूह डॉ. सुरजीत एस. भल्ला की अध्यक्षता में कार्य करेगा।
- **TEG का दायित्व**:
  - परिभाषाओं, अवधारणाओं, सर्वेक्षण उपकरणों और नमूना विधियों को अंतिम रूप देना,
  - अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना ताकि पहले की तरह की आय की कम रिपोर्टिंग को सुधारा जा सके,
  - आकलन विधियों, डेटा गुणवत्ता प्रोटोकॉल, परिणामों के अंतिम रूप और प्रकाशन की समय-सीमा का मार्गदर्शन करना,
  - वेतन और आय पर तकनीकी प्रभावों को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल टूल्स को अपनाना।

घरेलू आय सर्वेक्षण का महत्व

- **आय वितरण की प्रथम सटीक मैपिंग**: दशकों से खपत, गरीबी और रोजगार पर आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन भारत में अब तक घरेलू आय स्तर एवं वितरण पर आधिकारिक आँकड़े नहीं हैं।
  - यह सर्वेक्षण इस महत्वपूर्ण कमी को पूरा करेगा और नीति निर्माताओं को आय असमानता, क्षेत्रीय विषमताओं एवं आर्थिक विकास के वास्तविक प्रसार को समझने में मदद करेगा।
- **कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य निर्धारण**: सरकार इस सर्वेक्षण के माध्यम से सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से डिज़ाइन और कार्यान्वित कर सकेगी, जिससे प्रमाण-आधारित और समावेशी नीति-निर्माण संभव होगा।
- **प्रौद्योगिकी के प्रभाव का विश्लेषण**: यह सर्वेक्षण डिजिटल प्लेटफॉर्म, गिग कार्य, स्वचालन और अनौपचारिक रोजगार से घरेलू आय पर होने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करेगा, जो वर्तमान डेटा सेट में उपेक्षित रहा है।
- **राजकोषीय और कर नीति के लिए मानदंड**: यह सर्वेक्षण विभिन्न क्षेत्रों एवं वर्गों में वास्तविक आय प्रवाह को दर्ज कर कर नीति निर्धारण, आय वर्ग निर्धारण

और राजकोषीय पुनर्वितरण की रणनीतियों के लिए यथार्थपरक आधार प्रदान कर सकता है।

- **अंतरराष्ट्रीय तुल्यता**: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश नियमित रूप से ऐसे आय सर्वेक्षण करते हैं।

सर्वेक्षण संचालन की चुनौतियाँ

- **प्रकटन में संकोच**: घरेलू आय विशेषकर नकद या अनौपचारिक स्रोतों से होने वाली आय को लोग प्रायः कम बताते हैं या छुपाते हैं, जिससे कर या कानूनी कार्रवाई का डर रहता है।
- **जटिल और विविध आय स्रोत**: भारतीय परिवारों की आय कृषि, दिहाड़ी मजदूरी, प्रेषण, अनौपचारिक व्यापार और पेंशन जैसे अनेक और विखंडित स्रोतों से आती है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में इन स्रोतों को दर्ज करना और सत्यापित करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है।
- **आय, उपभोग और बचत के बीच विसंगति**: विगत सर्वेक्षणों में देखा गया कि रिपोर्ट की गई आय कुल उपभोग और बचत से कम थी, जो या तो स्मृति दोष या जानबूझकर गलत रिपोर्टिंग का संकेत देती है।
- **आय में मौसमी और अस्थिर उतार-चढ़ाव**: कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों में आय महीनों या मौसम के अनुसार काफी बदलती है।
  - एक बार किया गया सर्वेक्षण इन बदलावों को दर्ज नहीं कर पाएगा जब तक कि यह दीर्घकालिक या दोहराया न जाए।
- **फील्ड सर्वेक्षणकर्ताओं का प्रशिक्षण**: विश्वसनीय आय डेटा एकत्र करने के लिए ऐसे सर्वेक्षणकर्ताओं की आवश्यकता होगी जो जटिल साक्षात्कारों को सहजता से संचालित कर सकें, साथ ही प्रश्न पूछने में संवेदनशीलता और विश्वास बनाने की क्षमता रखते हों।

आगे की राह

- **सर्वेक्षण का संस्थानीकरण**: यह केवल एक बार की गतिविधि न होकर, नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए ताकि समय के साथ रुझानों को ट्रैक किया जा सके और दीर्घकालिक नीति-निर्धारण को बेहतर बनाया जा सके।
- **फील्ड जांचकर्ताओं का गहन प्रशिक्षण अनिवार्य है**— न केवल तकनीकी विधियों में, बल्कि प्रतिभागियों से विश्वास स्थापित करने, संवेदनशील आय संबंधित प्रश्न पूछने और स्थानीय आय संरचनाओं को समझने में भी।

Source: PIB

भारत-आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा

संदर्भ

- विगत एक वर्ष में, भारत ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नौ बैठकें की हैं, लेकिन किसी भी बिंदु पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

परिचय

- मूल समझौता 2009 में हस्ताक्षरित हुआ था।
- भारत ने ASEAN देशों के लिए अपने 71% टैरिफ लाइनों को खोला, जबकि इंडोनेशिया ने 41%, वियतनाम ने 66.5% और थाईलैंड ने 67% टैरिफ लाइनों को खोला।
- विगत 15 वर्षों में भारत का ASEAN को निर्यात दोगुना हुआ है, लेकिन आयात तीन गुना बढ़ गया है।
  - इन कारणों से समझौते की समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत हुई।
  - संयुक्त समिति द्वारा यह समीक्षा 2024 में शुरू हुई थी।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का संगठन (ASEAN)

- **स्थापना:** 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में। संस्थापक देश: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।
- **उद्देश्य:** शीत युद्ध के तनाव के बीच क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देना।

- **मुख्यालय:** जकार्ता, इंडोनेशिया।
- **वर्तमान सदस्य:** ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।

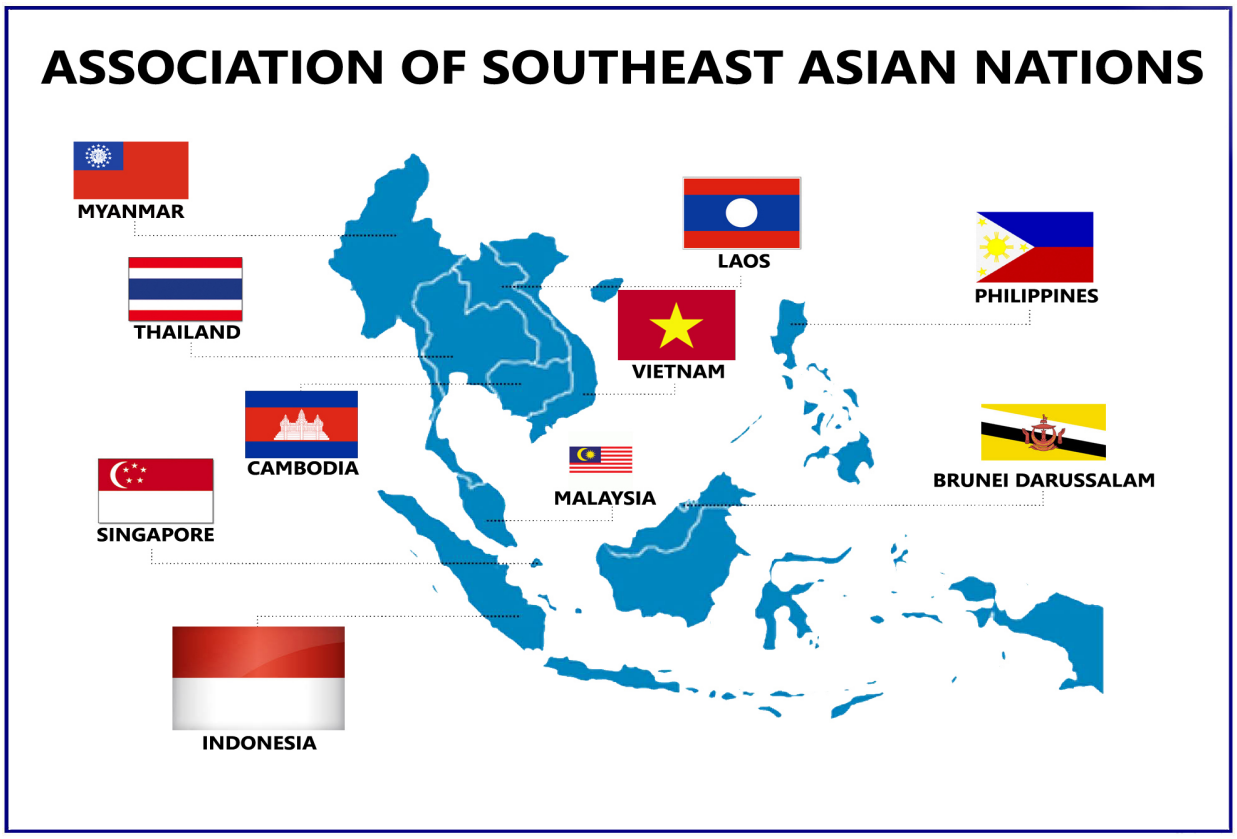

- ASEAN भारत, चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ आदि जैसे कई देशों और संगठनों के साथ संवाद साझेदार बनाए रखता है।

भारत-ASEAN संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **आधार**: सहयोग की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, जो साझा आर्थिक और रणनीतिक हितों पर आधारित थी तथा क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव की प्रतिक्रिया भी थी।
- **नीति ढांचा**: 1990 के दशक में "लुक ईस्ट नीति" की शुरुआत हुई, जिसे 2014 में "एक्ट ईस्ट नीति" में रूपांतरित किया गया—ASEAN से संबंधों को गहराई देने के लिए अधिक क्रियाशील दृष्टिकोण।
- **साझेदारी की प्रमुख उपलब्धियाँ**:
  - 1992: भारत बना सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर
  - 1996: पूर्ण संवाद साझेदार का दर्जा
  - 2012: रणनीतिक साझेदारी में उन्नयन
  - 2022: व्यापक रणनीतिक साझेदारी का स्तर प्राप्त
- **व्यापार और निवेश**: भारत और ASEAN ने एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे व्यापार और निवेश में काफी बढ़ोतरी हुई है।
  - ASEAN भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, और 2021-22 में कुल व्यापार US$110.4 बिलियन तक पहुँच गया।
- **क्षेत्रीय संपर्क**: भारत ASEAN से संपर्क बढ़ाने के लिए भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहा है।

- **रक्षा और सुरक्षा**: ASEAN-भारत समुद्री अभ्यास और ASEAN रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM+) में भागीदारी जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों से दोनों के बीच रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं।
  - भारत अपने इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण (SAGAR – क्षेत्र के लिए सुरक्षा और विकास) में ASEAN को प्रमुख स्थान देता है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग**: ASEAN छात्र विनिमय कार्यक्रम, ASEAN राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण और ASEAN-भारत थिंक टैंक्स नेटवर्क जैसी सांस्कृतिक पहलों के माध्यम से जन-जन के संबंधों को मजबूत किया गया है।

भारत-ASEAN मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- आसियान और भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग पर रूपरेखा समझौते पर 2003 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने बाद के समझौतों के लिए कानूनी आधार स्थापित किया।
  - इन समझौतों में वस्तुओं के व्यापार पर समझौता, सेवाओं के व्यापार पर समझौता और निवेश पर समझौता शामिल है, जो मिलकर आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (AIFTA) बनाते हैं।
- आसियान-भारत वस्तुओं के व्यापार पर समझौता 2010 में हस्ताक्षरित हुआ और प्रभावी हुआ।
  - इस समझौते के अंतर्गत , आसियान के सदस्य देशों और भारत ने 76.4% वस्तुओं पर टैरिफ को कम करके और समाप्त करके धीरे-धीरे अपने बाजारों को खोलने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- 2014 में हस्ताक्षरित आसियान-भारत सेवाओं के व्यापार समझौते में पारदर्शिता, घरेलू विनियमन, बाजार पहुंच, राष्ट्रीय उपचार, मान्यता और विवाद निपटान पर प्रावधान शामिल हैं।
- 2014 में हस्ताक्षरित आसियान-भारत निवेश समझौता भी निवेशकों के लिए उचित और न्यायसंगत उपचार, अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण के मामलों में गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार और उचित मुआवजे की गारंटी सहित निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

AIFTA से संबंधित चुनौतियाँ

- **बढ़ता व्यापार घाटा**: FTA के बाद से भारत का ASEAN के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ा है।
  - निर्यात की तुलना में ASEAN से आयात तेज़ी से बढ़ा, जिससे असमान लाभ हुए।
  - FY13 में $8 बिलियन का घाटा FY23 में $44 बिलियन तक पहुँच गया।
- **भारतीय सेवाओं को सीमित पहुंच**: सूचना प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाएँ और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में ASEAN ने उदारीकरण सीमित किया, जबकि भारत की इन क्षेत्रों में विशेषता है।
- **गैर-शुल्क बाधाएँ (NTBs)**: ASEAN देश जटिल मानक, लाइसेंसिंग आवश्यकताएं और अन्य नियामक प्रतिबंध लागू करते हैं, जो विशेष रूप से कृषि और फार्मास्युटिकल निर्यात को बाधित करते हैं।
- **मूल देश नियमों की समस्याएँ**: ढीले नियमों के कारण चीन जैसे तीसरे देश ASEAN के माध्यम से भारत में वस्तुओं का निर्यात करते हैं और टैरिफ लाभ उठाते हैं, जिससे मेक इन इंडिया के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को नुकसान होता है।
- **भारतीय कृषि को सीमित लाभ**: भारतीय कृषि उत्पाद उच्च स्वास्थ्य और वनस्पति मानकों व कोटा सीमाओं का सामना करते हैं।
  - वहीं, ASEAN से सस्ता पाम ऑयल, रबर और मसाले आयात किए जाते हैं, जिससे भारतीय किसानों पर असर पड़ता है।
- **वार्ता में असंतुलन**: ASEAN एक समूह के रूप में वार्ता करता है, जबकि भारत अकेले करता है, जिससे उसे अपेक्षित रियायतें प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

आगे की राह

- भारत और ASEAN ने 2022 में FTA की समीक्षा पर सहमति जताई ताकि असंतुलनों को संबोधित किया जा सके।

- सुदृढ़ सुरक्षा उपाय और कड़े मूल देश नियमों की आवश्यकता है।
- भारत की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व को देखते हुए ASEAN के साथ मजबूत साझेदारी दोनों के लिए लाभप्रद होगी और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रोत्साहित करेगी।
- 2024 से भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अपनी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

Source: TH

यीस्ट से पता चलता है कि भौतिकी उत्परिवर्तन के बिना बहुकोशिकीय जीवन को जन्म दे सकती है

संदर्भ

- नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज़ (NCBS) के वैज्ञानिकों द्वारा स्नोफ्लेक यीस्ट पर एक नए अध्ययन ने यह दिखाया है कि विकास की प्रक्रिया में बड़े बदलाव कैसे प्रारंभिक चरणों में एक पारंपरिक दृष्टिकोण से हटकर हो सकते हैं।

यीस्ट क्या है?

- यीस्ट एक एककोशिकीय कवक (फंगस) है। सामान्यतः उपयोग में:
  - **बेकिंग में** (ब्रेड को फूलाने के लिए)
  - **अल्कोहल निर्माण में** (किण्वन प्रक्रिया में)
  - **वैज्ञानिक शोध में** (मॉडल जीव के रूप में)
- **कलिका द्वारा प्रजनन (Reproduction by budding)**
  - एक छोटी कलिका (bud) माता कोशिका पर विकसित होती है।
  - केंद्रक विभाजित होता है, और इसका एक भाग कलिका में जाता है।
  - कलिका बढ़ती है और अलग होकर एक नई यीस्ट कोशिका बन जाती है।

स्नोफ्लेक यीस्ट क्या है?

- साधारण यीस्ट एकल कोशिकाओं के रूप में बढ़ता है, जिसमें कलिकाएँ बनने के बाद अलग हो जाती हैं।
  - स्नोफ्लेक यीस्ट में एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन (mutation) होता है, जो कलिकाओं को अलग नहीं होने देता।
- इसके कारण कोशिकाएँ एक-दूसरे से चिपकी रहती हैं और बर्फ के फाहे (स्नोफ्लेक) जैसी संरचना बनाती हैं।
  - ये समूह तेजी से बढ़ते हैं और केवल 12 घंटे के अन्दर नग्न आंखों से दिखाई देने लगते हैं।
- **वैज्ञानिक महत्व**: स्नोफ्लेक यीस्ट का उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि एककोशिकीय जीवन कैसे बहुकोशिकीय जीवों में विकसित हुआ।
  - सामान्यतः, बहुकोशिकीय जीवन में पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशेष जैविक प्रणालियों की आवश्यकता होती है (जैसे रक्त वाहिकाएं)।
  - परंतु स्नोफ्लेक यीस्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने के बावजूद यह तीव्रता से बढ़ता है।

वैज्ञानिक पहेली

- वर्तमान समझ के अनुसार, वृद्धि तब रुक जानी चाहिए जब आंतरिक कोशिकाओं को पोषण मिलना बंद हो जाए।
- लेकिन प्रयोगशाला में स्नोफ्लेक यीस्ट अपेक्षित सीमा से अधिक बढ़ता गया।
- वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि पोषक तत्व सभी कोशिकाओं तक कैसे पहुँच रहे हैं।

नई खोज — वृद्धि के पीछे भौतिक प्रक्रिया

- अध्ययन से पता चला कि वृद्धि में मदद करने वाली एक सरल भौतिक प्रक्रिया है: **तरल प्रवाह (fluid flow)**।
- वृद्धि केवल तरल माध्यम (solution) में देखी गई, जेल-जैसे माध्यम में नहीं। तरल में दो प्रकार की गति होती है:
  - **प्रसरण (Diffusion)**: पोषक तत्व उच्च से निम्न सांद्रता की ओर फैलते हैं।
  - **अड्वेक्शन (Advection)**: पूरा द्रव गति करता है और साथ में पोषक तत्व भी ले जाता है।

- सिर्फ प्रसरण बड़ी वृद्धि को नहीं समझा सकता (केवल लगभग 50 माइक्रोमीटर तक)।
- वैज्ञानिकों ने **अड्वेक्शन** देखा — तरल क्लस्टर के किनारों से अंदर गया और ऊपर से बाहर निकला।
- स्नोफ्लेक यीस्ट ग्लूकोज (चीनी) का उपभोग करता है और शराब तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है।
- इससे आसपास का तरल हल्का (कम घनत्व वाला) हो जाता है।
  - कम घनत्व वाला तरल ऊपर उठता है (जैसे गर्म हवा उठती है)।
  - यह प्रवाह नए पोषक तत्व क्लस्टर में लाता है, जिससे सभी कोशिकाएँ जीवित रहती हैं।

विकासीय महत्व

- पारंपरिक रूप से, बहुकोशिकीयता को क्रमिक आनुवंशिक परिवर्तनों से उत्पन्न माना जाता है।
- यह अध्ययन दर्शाता है कि **भौतिकी और रसायन** की प्रक्रियाएं ही प्रारंभिक बहुकोशिकीयता को संभव बना सकती थीं — आनुवंशिक परिवर्तन से पूर्व।
- बाद में, **आनुवंशिक विकास** इस बहुकोशिकीयता को जीवन की स्थायी विशेषता बना सकता है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

अम्बुबाची मेला

संदर्भ

- हज़ारों श्रद्धालु असम में कामाख्या मंदिर के वार्षिक अंबुबाची मेले के लिए एकत्र हुए हैं।

अंबुबाची मेला के बारे में

- यह पर्व मानसून के दौरान, सामान्यतः जून में, कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है — यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित एक पूज्य स्थल है, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है।
- यह मेला उर्वरता, मानसून की शुरुआत, और उन ऐतिहासिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है जो पृथ्वी को एक उर्वर महिला के रूप में दर्शाते हैं।
- 'अंबुबाची' शब्द का शाब्दिक अर्थ है *जल का प्रवाह*।

कामाख्या मंदिर

- गुवाहाटी, असम के नीलाचल पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक प्राचीन और अत्यंत पूज्य स्थल है।
- मुख्य मंदिर के चारों ओर दस महाविद्याओं को समर्पित व्यक्तिगत मंदिर स्थित हैं: काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका।
- वर्तमान मंदिर संरचना 1565 ई. में 11वीं–12वीं शताब्दी के एक पत्थर के पुराने मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके पुनर्निर्मित की गई थी।
- वास्तुकला की दृष्टि से, यह मंदिर दो शैलियों का अद्वितीय समावेश है — पारंपरिक नागर (उत्तर भारतीय) और सरसेनिक (मुगल) शैली।
- इस प्रसिद्ध शक्ति स्थल पर इस असामान्य संयोजन की उपस्थिति के कारण इसे *नीलाचल वास्तुकला शैली* कहा जाता है।

Source: IE

सुवर्णरेखा नदी

संदर्भ

- सुबर्णरेखा नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण ओडिशा के बालासोर ज़िले के कई गांवों में पानी घुस गया, जिससे 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए।

सुबर्णरेखा नदी के बारे में

- **उत्पत्ति**: झारखंड के रांची ज़िले के नागड़ी गाँव के पास, छोटानागपुर पठार से।
- **प्रवाह**: यह एक पूर्वमुखी नदी है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है।

- यह ओडिशा के तालसरी के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

- **मुख्य सहायक नदियाँ**: खरकाई, रोरो, कांची, हरमु नदी, डमर, कर्रू, चिंगुरू, करकारी, गुरमा, गर्रा, सिंगाडूबा, कोडिया, दुलुंगा और खैजोरी।
- **नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर**: रांची, जमशेदपुर, घाटशिला (झारखंड) और बालेश्वर (ओडिशा)।
- **हुण्डरू जलप्रपात**: यह एक प्रमुख जलप्रपात है जहाँ नदी रांची के पास 98 मीटर की ऊँचाई से गिरती है।

Source: TH

कतर

समाचार में

- ईरान ने अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के प्रतिशोध में क़तर स्थित अल-उदीद एयर बेस और इराक के ऐन अल-असद बेस पर मिसाइल हमले किए।
  - क़तर ने ईरान के हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि वह प्रतिक्रिया दे सकता है।

क़तर (दोहा (अल-दौहा))

- यह फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित एक स्वतंत्र अमीरात है।
- यह पूर्वी सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है जहाँ प्रायद्वीप मुख्य भूमि से मिलता है, और यह संयुक्त अरब अमीरात के उत्तर और पश्चिम में स्थित है।

  - बहरीन का द्वीप देश क़तर के उत्तर-पश्चिम में लगभग 25 मील (40 किमी) की दूरी पर है।
- क़तर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन व निर्यात पर आधारित है।
- क़तर का आधिकारिक धर्म इस्लाम है और शरिया यहाँ के समस्त राज्य विधान का आधार है।
  - हालाँकि, क़तर विभिन्न धर्मों का पालन करने वाली एक विविध जनसंख्या का घर है।
- अरबी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन अंग्रेज़ी पूरे देश में व्यापक रूप से द्वितीय भाषा के रूप में उपयोग की जाती है।

Source: TH

'नव्या' पहल

समाचार में

- महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के सहयोग से **नव्या पहल** की शुरुआत की।
- **नव्या (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण)** यह एक पायलट पहल है जिसका उद्देश्य 16–18 वर्ष की उम्र की (कम से कम 10वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त) किशोरियों को गैर-पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में कौशल प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य किशोरियों को **कौशल, आत्मविश्वास और अवसरों** से सशक्त बनाना है, ताकि वे **विकसित भारत@2047** और आत्मनिर्भर, समावेशी भविष्य के दृष्टिकोण में योगदान दे सकें।
- यह पहल **19 राज्यों के 27 जिलों** में लागू की जा रही है, जिसमें आकांक्षी ज़िले और पूर्वोत्तर राज्य सम्मिलित हैं — यह एक समावेशी और लक्षित दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- यह **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** और **पीएम विश्वकर्मा** जैसी मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाएगी।

Source :PIB

ई-रक्त कोष

संदर्भ

- स्वास्थ्य मंत्रालय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री (Rare Donor Registry) को राष्ट्रीय ऑनलाइन रक्त बैंक प्रबंधन मंच **ई-रक्तकोष (e-Rakt Kosh)** के साथ एकीकृत कर रहा है।
- इस एकीकरण से दुर्लभ रक्त समूह वाले लोगों को एक केंद्रीकृत प्रणाली तक पहुँच प्राप्त होगी, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHS) के अंतर्गत विकसित किया गया है।
- यह प्रणाली देशभर में रक्त बैंकों, रक्त की उपलब्धता और रक्तदान शिविरों की जानकारी प्रदान करेगी।

ई-रक्तकोष

- यह भारत में रक्त बैंकों और रक्त की उपलब्धता से संबंधित जानकारी का एक राष्ट्रीय मंच है और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ब्लड सेल पहल के अंतर्गत **सी-डैक** द्वारा विकसित किया गया है।
- यह भारत में सभी रक्त-संबंधी सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल है।

दुर्लभ रक्त समूह (Rare Blood Group)

- दुर्लभ रक्त समूह वह होता है जो किसी विशेष जनसंख्या में प्रति 1,000 लोगों में से एक से भी कम में पाया जाता है।
- इसकी दुर्लभता जातीयता, क्षेत्र, और लाल रक्त कोशिकाओं पर उपस्थित या अनुपस्थित विशिष्ट प्रतिजनों (antigens) पर निर्भर करती है।
- जब किसी व्यक्ति में सामान्य प्रतिजन नहीं होते या उसमें असामान्य प्रतिजन संयोजन होते हैं, तो उसका रक्त समूह दुर्लभ हो सकता है।
- दुर्लभ रक्त समूहों के उदाहरण जिनमें उच्च प्रचलन वाले प्रतिजन नहीं होते, उनमें शामिल हैं: **Rhnull**, **बॉम्बे (Oh)**, **Jr(a-)** आदि।

Source: TH

वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार

समाचार में

- गैर-संचारी रोगों के लिए WHO के वैश्विक राजदूत ने डब्लिन में आयोजित विश्व तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन के दौरान **2025 के ब्लूमबर्ग फिलान्थ्रॉपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड्स** के विजेताओं की घोषणा की।

समाचार के बारे में

- इन पुरस्कारों के माध्यम से भारत, मॉरीशस, मेक्सिको, मोंटेनेग्रो, फिलीपींस एवं यूक्रेन की सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को तंबाकू नियंत्रण के सिद्ध उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने की उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।
- ब्लूमबर्ग ने यह भी घोषणा की कि वह कम और मध्यम आय वाले देशों में तंबाकू नियंत्रण प्रयासों को तीव्र करने के लिए **20 मिलियन डॉलर के नए एक्सेलेरेटर फंड** की शुरुआत करेगा, जहाँ प्रगति ठप हो गई है।

ब्लूमबर्ग फिलान्थ्रॉपीज

- यह संगठन विश्व भर के **700 शहरों और 150 देशों** में निवेश करता है ताकि **पाँच प्रमुख क्षेत्रों** — कला, शिक्षा, पर्यावरण, सरकारी नवाचार, और सार्वजनिक स्वास्थ्य — पर ध्यान केंद्रित कर जीवन को बेहतर बनाया जा सके।
- **ब्लूमबर्ग फिलान्थ्रॉपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड्स** की शुरुआत 2009 में मुंबई में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन (तंबाकू या स्वास्थ्य पर) में हुई थी, और 2025 से पहले इसका अंतिम आयोजन 2018 में केप टाउन में हुआ था।

Source: TH

ग्वाडा नेगेटिव

संदर्भ

- फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी, एटाब्लिस्मां फ्रांसे डू साँग (Établissement Français du Sang / EFS) ने एक पूरी तरह से नया रक्त समूह प्रणाली की पहचान की है, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय रक्त संक्रमण संघ (ISBT) द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है।

परिचय

- इस नए रक्त समूह का नाम EMM-नेगेटिव रखा गया है और इसे अनौपचारिक रूप से "ग्वाडा नेगेटिव" कहा जाता है, जो उस महिला की ग्वाडेलूपीय उत्पत्ति का संदर्भ है, जिसमें यह रक्त प्रकार पाया गया है।
- जून 2025 तक, दुनिया में केवल एक व्यक्ति के पास यह रक्त प्रकार ज्ञात है, जिससे यह अब तक का सबसे दुर्लभ रक्त समूह बन गया है।
- ग्वाडा नेगेटिव नाम इस नववर्गीकृत EMM-नेगेटिव रक्त समूह प्रणाली का अनौपचारिक नाम है, जिसे ISBT ने आधिकारिक रूप से ISBT042 के रूप में दर्ज किया है।
- यह उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें EMM प्रतिजन (antigen) की अनुपस्थिति होती है, जो सामान्यतः लाल रक्त कोशिकाओं पर पाया जाता है और एक उच्च प्रचलन वाला प्रतिजन माना जाता है।
- उच्च प्रचलन वाले प्रतिजन लगभग सभी मनुष्यों में उपस्थित होते हैं, अतः इस तरह की अनुपस्थिति अत्यंत दुर्लभ और चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण होती है।
- नई प्रणाली किसी रक्त समूह को एक नई प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होता है:
  - यह आनुवंशिक रूप से निर्धारित और विरासत में प्राप्त होना चाहिए,
  - इसे सेरोलॉजिकल (रक्त सीरम आधारित) या आणविक तकनीकों से पहचाना जा सके,
  - इससे संबंधित एक एंटीबॉडी उपस्थित हो — और EMM-नेगेटिव इन सभी मानदंडों पर खरा उतरता है।
- EMM-नेगेटिव रक्त प्रकार की पहचान अब तक ज्ञात 47 रक्त समूह प्रणालियों में एक नई 48वीं वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त प्रणाली के रूप में जुड़ गई है, जो रक्त संक्रमण विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है।

अंतर्राष्ट्रीय रक्त संक्रमण संघ (ISBT)

- **ISBT की स्थापना** 1935 में हुई थी, जिससे यह संक्रमण चिकित्सा (transfusion medicine) के क्षेत्र में सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है।
- **मुख्यालय:** एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स।
- **कार्य:** यह एक वैश्विक वैज्ञानिक संस्था है जो रक्त संक्रमण चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है।
  - ISBT को मानकीकृत रक्त समूह शब्दावली प्रणाली को विकसित और बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्था माना जाता है।

Source: TH

भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की आलोचना की

संदर्भ

- भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में देश के संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और उन्हें अनुचित एवं तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है।
  - भारत ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद पर OIC की चुप रहने की निंदा की है और इसे वैश्विक आतंकवाद विरोधी सहमति की अवहेलना करार दिया है।

इस्लामी सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation – OIC)

- **उद्देश्य:** यह संगठन स्वयं को "इस्लामी जगत की सामूहिक आवाज़" कहता है और "अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देने की भावना के साथ मुस्लिम जगत के हितों की रक्षा और संरक्षण" के लिए कार्य करता है।

- **सदस्य:** 57 सदस्य राष्ट्र (प्रमुख रूप से मुस्लिम बहुल देश)।
  - भारत OIC का सदस्य नहीं है, बावजूद इसके कि उसके पास विश्व में तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है।
- **आधिकारिक भाषाएँ:** अरबी, अंग्रेज़ी और फ्रेंच।
- **मुख्यालय:** जेद्दाह, सऊदी अरब।
- OIC एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी।

Source: AIR

इफको, ब्राजील में प्रथम विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी

संदर्भ

- भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था (IFFCO) ब्राज़ील में अपना प्रथम विदेशी **नैनो उर्वरक संयंत्र** स्थापित कर रही है।
  - यह संयंत्र प्रति वर्ष **45 लाख लीटर नैनो उर्वरक** का उत्पादन करेगा।

नैनो उर्वरक

- नैनो उर्वरक एक ऐसा उर्वरक होता है जिसमें पोषक तत्वों के कण **नैनोमीटर आकार** (सामान्यतः 100 नैनोमीटर से कम) के होते हैं।
- ये उर्वरक छोटे आकार, उच्च सतह क्षेत्रफल और बेहतर अवशोषण के कारण पौधों को पोषक तत्व अधिक कुशलता से प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।
- नैनो उर्वरक **सटीक कृषि (प्रेसिशन एग्रीकल्चर)** का हिस्सा होते हैं, जिनका उद्देश्य पोषक तत्वों की हानि को कम करना और उत्पादकता बढ़ाना है।
- भारत **IFFCO (इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र को-ऑपरेटिव लिमिटेड)** द्वारा विकसित **नैनो यूरिया** को 2021 में मंजूरी देने और व्यावसायिक रूप से अपनाने वाला **प्रथम देश** बना।
  - नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के उपयोग को कम करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि पारंपरिक यूरिया पर **भारी सब्सिडी** दी जाती है और इसका अत्यधिक उपयोग होता है।

Source: TH

■■■■